INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Representations from Association of Indian Fishery Industry have been received requesting rehabilitation of the sick deep-sea fishing units.

(b) No, Sir.

(c) No legal constraint is envisaged in implementation of rehabilitation package announced in April, 1991 which was further liberalised in June, 1992.

Licences for brewing beer

283. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain State Government have issued licences for brewing beer whereas the Central Government propose to delicence the Beer Industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) Government's reaction with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) According to the legal position, the Central Government alone is competent to issue a licence for brewing beer. However, it is a fact that certain State Governments have issued permissions for installing breweries. The detailed information regarding these permissions is being collected from the States and will be laid on the Table of the House as soon as it is available. Government will also finalise its reaction after full information is available.

At present there is no proposal under consideration with the Government to delicense beer industry.

रोजगार समस्या हल करने के लिए कृषि उद्योग

284. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1993 के "आब्जर्वर" में एग्रो-इंडस्ट्री कैन सोल्व इंडियाज जाब प्राब्लम ए स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार और विकास करके देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को हल किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए इस उद्योग में कितनी पूंजी का निवेश किये जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है । यह अनुमान है कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने से इन उद्योगों में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान करीब 10 लाख श्रम वर्ष (मैन-इयर्स, के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा ।

खाद्य क्षेत्रों की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

285. श्री राम जेठमलानी ;
श्रीमती सुषमा स्वराज ;

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1993 के "दि इक्नोमिक टाइम्स" में,